



मौद्रिक नीतिसमीक्षा अगस्त 2019

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हुई मौद्रिक नीतिसमितिकी बैठक में [भारतीय रज़िर्व बैंक](#) (Reserve Bank of India- RBI) ने रेपो दर (Repo Rate) में 35 आधार अंकों अर्थात् 0.35% की कटौती की है। यह लगातार चौथी बार है जब भारतीय रज़िर्व बैंक ने रेपो दर को कम किया है।

प्रमुख नरिणयः

रेपो दर में कमी

- रेपो दर को 5.75% से कम कर 5.40 % कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि यह पछिले नौ वर्षों के दौरान सबसे कम रेपो दर है।
- RBI ने वर्ष 2019-20 के लिये अर्थव्यवस्था की विकास दर यानी सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धिदर का अनुमान 7% से घटाकर 6.9% कर दिया है।

24 घंटे NEFT की सुवधि

- मौद्रिक नीतिसमितिकी बैठक में नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम (National Electronic Fund Transfer System- NEFT) बारे में यह घोषणा की गई है कि दिसंबर 2019 से NEFT की सुवधि सप्ताह के सभी दिनि 24 घंटे उपलब्ध रहेगी।
 - नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) धन प्रेषण या हस्तांतरण का एक लोकप्रिय माध्यम है। इसकी वशिषता यह है कि, इसमें न्यूनतम और अधिकतम राशा की कोई सीमा नरिधारति नहीं है।
 - इस प्रणाली का दोष यह है कि इसके द्वारा धन राशा का हस्तांतरण सभी कार्यदविसों (माह के दूसरे तथा चौथे शनविर को छोड़कर) के दौरान एक नरिधारति समय (8 A.M. से 7 P.M. तक) पर ही होता है।

NBFCs के लिये ऋण की उपलब्धता

- RBI ने बैंकों को यह अनुमति दी है कि बैंक कृषि, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) जैसे प्राथमिक क्षेत्रों को करज उपलब्ध कराने हेतु [गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों](#) (Non-Banking Financial Companies-NBFCs) को ऋण दें।
 - भारतीय रज़िर्व बैंक ने NBFCs में बैंकों के नविश की सीमा को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर शेयर पूंजी (टयिर-1) का 20 प्रतिशत करने की अनुमति दी है।
 - इसके तहत बैंक NBFC को 10 लाख रुपए तक कृषि (नविश ऋण), सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को 20 लाख रुपए तथा आवास के लिये प्रति करजदार 20 लाख रुपए तक (फलिहाल 10 लाख रुपए) के करज दे सकेंगे। इस श्रेणी के करज को प्राथमिक क्षेत्र के करज के अंतर्गत माना जाएगा।

सभी पुनरावृत्तीय बलियों BBPS के तहत कवर करने का नरिणय

- RBI ने सभी पुनरावृत्तीय बलि भुगतानों को भारत बलि भुगतान प्रणाली (Bharat Bill Payment System- BBPS) के तहत कवर करने का नरिणय लया है तथा इस संबंध में वसितृत दशा-नरिदेश जारी कये जाएंगे।
 - वर्तमान में BBPS के तहत केवल पाँच क्षेत्रों- डायरेक्ट-टू-होम, बजिली, गैस, टेलिकॉम और पानी के पुनरावृत्तीय बलि भुगतान को कवर किया जाता है।
 - भारत बलि भुगतान प्रणाली की संकल्पना भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI) द्वारा की गई थी और यह राष्ट्रीय भुगतान नगिम (NPCI) द्वारा संचालति है। यह लेन-देन की नश्चितीता, वशिषसनीयता और सुरक्षा के साथ पूरे भारत में सभी ग्राहकों को एक अंतर-सुलभ और अंतर-प्रचालनीय (interoperable) "किसी भी समय किसी भी स्थान से" बलि भुगतान की सेवा प्रदान करने वाली वन-स्टॉप प्रणाली है।
 - इसके द्वारा भुगतान के कई तरीके हैं और SMS या रसीद के माध्यम से भुगतान की तत्काल पुष्टि होती है।

मौद्रिक नीतिसमिति

मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee-MPC) भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति है जिसका गठन ब्याज दर निर्धारण को अधिक उपयोगी एवं पारदर्शी बनाने के लिये 27 जून, 2016 को किया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम में संशोधन करते हुए भारत में नीति निर्माण को नवगठित मौद्रिक नीति समिति (MPC) को सौंप दिया गया है।

- वित्त अधिनियम 2016 द्वारा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 (RBI अधिनियम) में संशोधन किया गया, ताकि मौद्रिक नीति समिति को वैधानिक और संस्थागत रूप प्रदान किया जा सके।
- भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, मौद्रिक नीति समिति के छह सदस्यों में से तीन सदस्य RBI से होते हैं और अन्य तीन सदस्यों की नियुक्ति केंद्रीय बैंक द्वारा की जाती है।
- रिज़र्व बैंक का गवर्नर इस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है, जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक के डप्टी गवर्नर मौद्रिक नीति समिति के प्रभारी के तौर पर काम करते हैं।

रेपो दर क्या है?

रेपो दर वह दर है, जिस पर बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक से ऋण लेते हैं। रेपो दर में कटौती कर RBI बैंकों को यह संदेश देता है कि उन्हें आम लोगों और कंपनियों के लिये ऋण को सस्ता करना चाहिये।

प्रभाव

- भारतीय के इस निर्णय का प्रभाव यह होगा कि अब बैंकों के पास आसान शर्तों पर कर्ज़ देने के लिये अधिक पैसा होगा। गौरतलब है कि कर्ज़ दरें सस्ती होने से अर्थव्यवस्था कुछ इस तरह से लाभान्वित होती है:
 - मकान, कार या अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के लिये कम ब्याज दर पर कर्ज़ उपलब्ध होता है।
 - जब ब्याज की दर कम होती है तो लोग खरीदारी के लिये उत्साहित होते हैं।
 - जब लोग खरीदारी के लिये उत्साहित होते हैं तो बाज़ार में मांग बढ़ती है।
 - जब बाज़ार में मांग बढ़ती है तो अधिक उत्पादन की स्थितियाँ बनती हैं।
 - जब अधिक उत्पादन की परस्थितियाँ बनती हैं, तब नविशक नए नविश के लिये प्रेरित होते हैं।
 - जब नविश बढ़ता है तो आर्थिक गतिविधियाँ तेज़ होती हैं।
 - जब आर्थिक गतिविधियाँ तेज़ होती हैं तो रोज़गार के अवसर भी बढ़ते हैं।

नष्िकर्ष

एक ऐसे समय में जब वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था की धीमी हो रही रफ़्तार के चलते व्यापार युद्ध की संभावनाएँ बढ़ रही हों; घरेलू स्तर पर भी महंगाई की दर काफी नीचे हो; शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही बाज़ारों में मांग में कमी हो रही हो; निर्यात तथा आयात दोनों में कमी हो रही हो, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उठाए गए कदम अर्थव्यवस्था के विकास को गति देने में सहायक हो सकते हैं बशर्ते बैंकों द्वारा रेपो दर में इस कटौती का लाभ ग्राहकों और उद्योगों को उपलब्ध कराया जाए।

स्रोत: द हट्टि, इंडियन एक्सप्रेस एवं अन्य